

न्यायालय, समाहर्ता, पश्चिम चम्पारण, बेतिया।  
न्यायालय वाद संख्या सी0आर0एम0 -20/2011-12

कमल राम बनाम सरकार

आदेश

Annexure-14

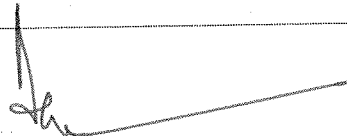
Sl. no of Order and Date	Order and officer Signature	Action taken on order and date
<u>28-10-2013</u>	<p>यह अपील कमल राम वल्द स्व0 सहदेव राम, ग्राम- मठिया, लौरिया द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, नरकटियागंज के आदेश दिनांक 22.05.2007 के उस आदेश के विरुद्ध दायर किया गया है जिसके द्वारा अपीलकर्ता के ज0वि0प0 के अनुज्ञप्ति संख्या 8/90 को रद्द कर दिया गया है।</p> <p>निम्न न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से ज्ञात होता है कि मंत्रीमंडल (नि0) विभाग के निगरानी अन्वेषण की टीम द्वारा जून 1997 से फरवरी 2002 तक लाल कार्डधारियों में खाद्यान्न उठाव की मात्रा, राशन कार्ड में प्रविष्टि की गणना एवं मिलान के जाँच के क्रम में पाया गया कि अपीलकर्ता द्वारा पंचायत मठिया, प्रखंड- लौरिया द्वारा उठाव किये गये खाद्यान्न का एक तिहाई भाग ही लाभुकों के बीच वितरण कर शेष दो तिहाई भाग खाद्यान्न को लाल कार्ड पर फर्जी एवं झुठी प्रविष्टि कर कालाबाजारी कर दी गई है। अनुमंडल पदाधिकारी, नरकटियागंज द्वारा अपीलकर्ता से स्पष्टीकरण की माँग की गई लेकिन उनके द्वारा तथ्य प्रारूप एवं संतोषजनक साक्ष्य समुचित अवसर दिये जाने के बावजूद भी प्रस्तुत नहीं करने के कारण अपीलकर्ता पर लगाये गये आरोप सत्य पाकर उनकी अनुज्ञप्ति संख्या 8/90 को रद्द कर दिया गया।</p> <p>इस आदेश के विरुद्ध अपीलकर्ता द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में एक रिट याचिका दायर की गई जिसका CWJC संख्या-7348/06 है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 03.04.2007 को आदेश पारित किया गया जिसके द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी के आदेश को रद्द करते हुए अपीलकर्ता के दावे पर विचार करने हेतु वाद को रिमांड कर दिया गया। साथ ही यह भी निदेश दिया गया कि उनके कारण पृच्छा पर पुनः विचार करते हुए उन्हें सुनवाई हेतु अवसर दिया जाय।</p> <p>माननीय उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, नरकटियागंज द्वारा अपीलकर्ता के पूर्व में पाई गई अनियमितता के संबंध में दिनांक 09.05.2007 को ठोस प्रमाण के साथ स्पष्टीकरण की माँग की गई है। अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा आदेश में उल्लेख किया गया है कि विक्रेता (अपीलकर्ता)</p>	

स्वयं उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किये परन्तु साक्ष्य के रूप में कोई कागजात दाखिल नहीं किया। अपीलकर्ता द्वारा उन्हें बताया गया कि वर्तमान में उनके पास न भंडार पंजी उपलब्ध है न वितरण पंजी उपलब्ध है। इस परिस्थिति में विक्रेता पर पूर्व में लगाये आरोप को सही पाते हुए उनकी अनुज्ञप्ति को पुनर्जीवित करने संबंधी आवेदन को अस्वीकार करते हुए अनुज्ञप्ति को दिनांक 22.05.2007 को रद्द कर दिया गया।

अपीलकर्ता द्वारा अपील में निम्नांकित तर्क दिया गया है :-

1. मंत्रीमंडल निगरानी विभाग, पटना द्वारा वर्ष 2003 में जॉच की गई एवं इस जनवितरण दुकान से संबंधित लाभुकों से सम्पर्क किया गया एवं सत्यापन किया गया कि जून 1997 से फरवरी 2002 तक विक्रेता द्वारा लाभुकों को सही तरीका से आपूर्ति नहीं की गई है। लाभुकों को मात्र एक तिहाई ही अनाज की आपूर्ति की गई है एवं शेष दो तिहाई अनाज को खुले बाजार में बेच दिया गया है। अपीलकर्ता का कहना है कि लाभुकों का न तो पूरा पता एवं नाम दिया गया है और उनके समक्ष जॉच भी नहीं की गई है।
2. अपीलकर्ता का कहना है कि किसी भी विक्रेता द्वारा छः वर्ष बाद यह बताना मुश्किल है कि कितनी बार उन्होंने खाद्यान्न का उठाव किया एवं कितनी बार कार्ड धारकों ने अनाज का उठाव किया।
3. अपीलकर्ता का यह कहना है कि उनके ग्राम में 1998 में आग लगी थी जिसमें उनके गाँव के सभी हरिजन का घर जल गये थे और अपीलकर्ता के राशन दुकान से संबंधित सभी कागजात जल गये थे।
4. अन्त में अपीलकर्ता का कहना है कि अनुमंडल पदाधिकारी बिना उन्हें सुनवाई हेतु प्रयाप्त अवसर दिये जॉच रिपोर्ट दिये एवं उनके कारण पृच्छा पर पूर्ण विचार किये ही आदेश पारित किया है जिसे रद्द करने हेतु अनुरोध किया गया है।


अनुमंडल पदाधिकारी, नरकटियागंज के आदेश दिनांक 22.05.2007 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि उन्होंने विक्रेता से जून-1997 से फरवरी-02 तक लाल कार्ड धारियों के वितरण हेतु उठाव किये गये खाद्यान्न की फर्जी प्रविष्टि कार्डों में उठाव किये गये खाद्यान्न का दो तिहाई भाग खाद्यान्न की कालाबाजारी की गयी है के संबंध में ठोस प्रमाण के संबंध में




स्पष्टीकरण की मांग की गयी। साथ ही विक्रेता को प्रसंगाधीन अवधि का भंडार पंजी , वितरण पंजी, केश मेमो के साथ स्वयं उपस्थित होने का निदेश दिया गया। आदेश में लिखित है कि विक्रेता स्वयं उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किये परंतु साक्ष्य के रूप में उन्होंने कोई कागजात दाखिल नहीं किया। अतः अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा आदेश दिया गया कि आवेदक द्वारा ठोस प्रमाण एवं साक्ष्य दाखिल नहीं किये जाने के कारण उन्हें दोष मुक्त करना न्यायोचित नहीं बताया गया है और इस आधार पर अनुज्ञप्ति को रद्द कर दिया गया है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि अनुमंडल पदाधिकारी, नरकटियागंज द्वारा अपीलकर्ता के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की जांच सही तरीके से नहीं की गयी है एवं यह भी उल्लेख नहीं किया गया है कि अपीलकर्ता द्वारा किन-किन कंडिकाओं का उल्लंघन किया गया है। अनुमंडल पदाधिकारी, नरकटियागंज के आदेश दिनांक 22.05.2007 को रद्द करते हुए वाद को उन्हें इस निदेश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि अपीलकर्ता को सुनवाई एवं प्रमाण दाखिल करने हेतु पर्याप्त अवसर देकर उनके उपर लगाये गये आरोपों के संबंध में आदेश पारित करें। निम्न न्यायालय के अभिलेख को वापस किया जाता है।

लेखापित्त एवं संशोधित

  
जिला दंडाधिकारी,  
पश्चिम चम्पारण, बेतिया।

  
जिला दंडाधिकारी,  
पश्चिम चम्पारण, बेतिया।